उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन

2138. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1985, 1986 और 1987 के वर्षों के दौरान उक्त राज्य में कुशल, अकुशल, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या में तुलनात्मक रूप में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है । और

(ग) सरकार किस प्रकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1983 के दौरान किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 83वें दौर से प्राप्त परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5+आयु के व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता (सामान्य मूल स्तर के अनुसार) इस प्रकार हैं :—

	पुरुष	महिला
ग्रामीण . . .	0.78	0.02
शहरी . . .	2.66	0.29

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के खंड 1 के अध्याय 3 में तथा खंड 11 के अध्याय 5 में दिए गए है जो उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि को बीजों की सप्लाई

2139. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986–87 और 1987–88 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तथा दिल्ली को क्रमशः कितने कितने मूल्य के बीज सप्लाई किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन राज्यों को बीज सप्लाई किए जाने से पूर्व बीजों की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई ;

(ग) 1986–87 में दिल्ली के किसानों को कितने मूल्य के खीरे के बीजों की सप्लाई की गई ; और

(घ) बीजों की सप्लाई के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) 1986–87 और 1987–88 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किए गए बीजों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(मूल्य लाख रुपए में)

राज्य	1986–87	1987–88 से फरवरी 1988 तक (अंतिम)
मध्य प्रदेश	93.83	45.06
दिल्ली	45.06	76.68
राजस्थान	95.51	69.60
उत्तर प्रदेश	380.82	157.76
बिहार	708.68	1256.99

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1986-87 में दिल्ली के किसानों को सप्लाई किए गए खीरे के बीज का मूल्य 67,479 रुपए है ।

(घ) भारत सरकार प्रत्येक बुवाई मौसम अर्थात् खरीफ और रबी/ग्रीष्म के एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीजों की मांग और उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सम्मेलन आयोजित करती है । राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म निगम आदि के माध्यम से बीजों की मांग तथा आपूर्ति के बीच का अन्तर पूरा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं

मिट्टी का कटाव

2140. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85, 1985-86 और 1987-88 के वर्षों के दौरान देश में क्रमश: कितने हेक्टेयर भूमि कटाव के कारण बरबाद हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार मिट्टी के कटावों को रोक पाने में विफल रही है ;

(ग) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या प्रयास किए गए और क्या क्या नीतियां बनाई गई ; और

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान मिट्टी के कटाव को रोक पाने में सरकार किस हद तक सफल हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :

(क) भू-क्षरण और भूमि का अवक्रमण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है । वृहत्त और पुन: सर्वेक्षण न किए जाने से वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक के दौरान देश में भू-क्षरण से प्रभावित भूमि को मात्रा संबंधी वर्षवार जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि विभिन्न अनुमानों, जिसमें राष्ट्रीय कृषि, आयोग (1976), राष्ट्रीय पिछडा क्षेत्र विकास समिति (1981), राष्ट्रीय वन आयोग (1980) और भू-उपयोग सांख्यिकी (1981-82)) के अनुमान शामिल हैं, से यह पता चलता है कि करीब 173 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र भू-क्षरण और विभिन्न प्रकार की भूमि के अवक्रमण से प्रभावित हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना से राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र मृदा में एवं जल संरक्षण कार्यक्रमशुरू किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 1986-87 के अंत तक 31.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नीचे दी गई हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के सवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(2) बाढ प्रवण नदियों के सवण क्षेत्रों में समेकित जल-विभाजक प्रबन्ध को केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल-विभाजक विकास कार्यक्रम ।

(4) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त—

(क) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में जल-विभाजक विकास मार्गदर्शी परियोजना ।

(ख) उत्तर प्रदेश में हिमालयी जल विभाजक प्रबन्ध ।

(5) यूरोपीय आर्थिक समदाय (ई० ई० सी०) से सहायता प्राप्त—

(क) उत्तर प्रदेश में चम्बल और यमुना के बीहड क्षेत्रों में समेकित जल-विभाजक प्रबध ।

(ख) गुजरात में समेकित जल-विभाजक प्रबन्ध परियोजना ।